नियमावली- 3

निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रिया का पालन किया जाता है

{धारा 4 (1) (बी) (iii)}

(ए) जांच : - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जांच एक अपराध के कमीशन के बारे में साक्ष्य एकत्र करना है

क्र. सं.	कार्यकलाप	कार्यवाही का स्तर	समय सीमा
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है (जांच अधिकारी)	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
2	साक्षी की परीक्षा	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
3	अपराध स्थल पर जांच अधिकारी का दौरा	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
4	सबूत का संग्रह	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
5	साइट योजना तैयार करना	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
6	आरोपियों की गिरफ्तारी	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
7	स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
8	पुलिस / न्यायिक हिरासत रिमांड प्राप्त करना	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
9	खोज	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
10	जब्ती	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है

		संहिता में निर्धारित है	संहिता में निर्धारित है
11	मामलों की डायरी तैयार करना	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
12	चार्जशीट दाखिल करना	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है

(बी) एसपीयूडब्लूएसी

महिलाओ और बच्चो के लिए विशेष पुलिस इकाई

क्र. सं.	कार्यकलाप	कार्यवाई का स्तर	समय सीमा
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है (जांच अधिकारी)	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
2	साक्षी की परीक्षा	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
3	अपराध स्थल पर जांच अधिकारी का दौरा	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
4	सबूत का संग्रह	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
5	साइट योजना तैयार करना	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
6	आरोपियों की गिरफ्तारी	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
7	स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
8	पुलिस / न्यायिक हिरासत रिमांड प्राप्त करना	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
9	खोज	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है

10	जब्तूी	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
11	मामलों की डायरी तैयार करना	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है
12	चार्जशीट दाखिल करना	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है	जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में निर्धारित है

(सी) पुलिस नियंत्रण कक्ष

गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार ने पुलिस, अग्निशमन और CAT एम्बुलेंस सहित सभी प्रकार की आपात स्थितियों और जिला कॉलों के लिए एकल आपातकालीन नंबर '112' के साथ ERSS को राष्ट्रव्यापी एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के रूप में लॉन्च किया है, पुलिस नियंत्रण कक्ष (PCR) वाहन निर्देशों पर कॉल करने वालों को सहायता प्रदान करते हैं। PSAP में मोबाइल गश्ती वैन (MPVs), पीसीआर नेट पर मोबाइल गश्ती मोटरसाइकिलें (MPMs), पराक्रम वैन (PDVs), प्रखर वैन, सभी महिला पीसीआर (AWPCR) और पर्यटक पुलिस वैन आदि शामिल हैं।

क्र.सं.	कार्यकलाप	कार्यवाइ का स्तर	समय सीमा
1.	केंद्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष एकीकृत कॉम्प्लेक्स ऑप्स. एवं कम्युनिकेशन, एफसी-50, शालीमार बाग, दिल्ली-110018 में चालू है। सीपीसीआर में संचार नेटवर्क में 15 PRI लाइनें शामिल हैं और इसमें 1090, 1091, 1093, 1096, 1291, 155270 के साथ 112/100 पर सार्वजनिक कॉल प्राप्त करने के लिए 122 परिचालन चैनल (450 तक विस्तार योग्य, जैसा कि ACD अधिकारियों द्वारा बताया गया है और ERSS-112, दिल्ली प्रणाली में सार्वजनिक सहायता के लिए 155271 सीधी हेल्पलाइन है।	पीसीआर वैन में स्टाफ तैनात	पीसीआर का औसत प्रतिक्रिया समय अब तक लगभग 07 मिनट है और यह सड़क और यातायात की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

(डी) सतर्कता

क्र. सं.	कार्यकलाप	कार्यवाइ का स्तर	समय सीमा
1	शिकायत और डायरी मिली	रोज़नामचा रखने वाला	दो दिन
2	अद्वितीय नंबर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रकोष्ठ में जाएगी शिकायत	आई/सी कंप्यूटर प्रकोष्ठ	एक दिन

3	जवाब प्रस्तुत करने के लिए शिकायत सम्बद्ध प्रधान सहायक के पास जाएगी	प्रधान सहायक	उसी दिन
4	शिकायत सम्बद्ध ईओ पास जाती है	ईओ	उसी दिन
5	पूछताछ पूरी हो जाएगी	ईओ के द्वारा	एक महिना
6	जांच रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाएगी	उपायुक्त पुलिस/ सतर्कता दिल्ली संयुक्त आयुक्त पुलिस/ सतर्कता आयुक्त पुलिस / दिल्ली	उसी दिन
7	कार्यवाई करने के लिए पूछताछ वापस मिली	उपायुक्त पुलिस/ सतर्कता	एक दिन
8	प्रधान सहायक द्वारा की गई कार्यवाई	प्रधान सहायक	आदेशों के अनुसार उसी दिन। 2/3 दिनों के भीतर कार्यवाई हो सकती है। डीई के मामले में एक अतिरिक्त सप्ताह की आवश्यकता हो सकती है।
9	आवेदक को जानकारी	प्रधान सहायक	चार सप्ताह के बाद।

(ई) यातायात

(ई) ट्रेफ़िक

क्रम.. सं.	गतिविधि	कार्रवाई का स्तर	निर्धारित समय - सीमा
1.	यातायात विनियमन	सभी यातायात अधिकारियों/कर्मियों एवं सिग्नलों द्वारा	चौबीसों घंटे
2.	सूचना – प्रवाह चार्ट नीचे दिया गया है:- I. ट्रेफ़िक अधिकारी को वोका ऐप (वॉयलेशन ऑन कैमरा ऐप) के माध्यम से उल्लंघन को पकड़ने के लिए ड्यूटी के विशेष बिंदु पर तैनात किया गया है। II. उल्लंघन की रिपोर्ट भी कैमरों के माध्यम से की जाती है। III. ट्रेफ़िक प्रहरी ऐप के माध्यम से जनता द्वारा।	I. यातायात पुलिस II. आरएलवीडी शाखा	चौबीसों घंटे
3.	I. सभी उल्लंघन प्रमाणीकरण के लिए स्वचालित रूप से सर्वर पर भेजे जाते हैं। Voca के मामले में, उल्लंघन की जाँच	I. सर्किल स्टाफ II. आरएलवीडी शाखा	चौबीसों घंटे

	सर्कल स्टाफ द्वारा की जाती है और रिपोर्ट अपराध नोटिस जनरेशन के लिए सर्वर पर भेजे जाते हैं। II. कैमरे और सार्वजनिक माध्यम से सूचित उल्लंघन की जांच आरएलवीडी शाखा द्वारा की जाती है।		
4.	उत्पन्न नोटिस को वाहन पोर्टल पर रिकॉर्ड के अनुसार, एसएमएस या स्पीड पोस्ट के माध्यम से वाहन के पंजीकृत मालिक को भेजा जाता है।	I. कंप्यूटर शाखा II. सूचना शाखा	I. गैर-समाधानीय अपराधों के लिए 15 दिनों के भीतर II. समझौता योग्य अपराधों के लिए 30 दिनों के भीतर
5.	नोटिस प्राप्त होने पर उल्लंघनकर्ता समझौता राशि जमा कर सकता है I. दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट पर ऑनलाइन। II. नोटिस शाखा, यातायात पुलिस मुख्यालय, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली में डीडी/चेक द्वारा III. सर्किल में ईचलान मशीन के माध्यम से	कंप्यूटर शाखा सूचना शाखा	2 से 3 दिन
6.	I. गैर-शमनीय नोटिस 15 दिनों के बाद न्यायालय को भेजे जाते हैं। II. कंपाउंडेबल नोटिस का भुगतान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है। उसके बाद इसे कोर्ट में भेजा जाता है।	एनआईसी के माध्यम से स्वचालित रूप से	I. नॉन-कंपाउंडेबल को 15 दिन बाद न्यायालय भेजा गया II. कंपाउंडेबल योग्य नोटिस 90 दिनों के बाद न्यायालय को भेजे जाते हैं
7.	दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट पर शिकायत निवारण की सुविधा उपलब्ध है। उल्लंघनकर्ता एसएमएस/प्रिंटेड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसकी जांच आरएलवीडी शाखा द्वारा की जाती है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है।	I. आरएलवीडी शाखा II. कंप्यूटर शाखा	15 दिनों के भीतर

(एफ) प्रावधान और रसद

क्र. सं.	कार्यकलाप	कार्यवाही का स्तर	समय सीमा
1	सभी जिला / इकाइयों से विभिन्न मदों के लिए मांगपत्र आमंत्रित	प्रभारी स्टोर	एक महीना
2	जिलों / इकाइयों की आवश्यकताओं के आधार पर समेकित मांग पत्र तैयार करने के लिए	प्रभारी स्टोर	एक सप्ताह में
3	निरीक्षक (प्रभारी) द्वारा पूरी तरह से जांच के लिए मांगपत्र निरीक्षक को प्रस्तुत करे	निरीक्षक	एक ही दिन

4	वरिष्ठ अधिकारियों को समेकित मांग पत्र अग्रेषित करें	निरीक्षक	अगले दिन
5	वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र की जांच करना तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु पुलिस मुख्यालय को अग्रेषित करने की सिफारिश करना	सहायक आयुक्त पुलिस, उपायुक्त पुलिस, अति. आयुक्त पुलिस और संयुक्त आयुक्त पुलिस	एक हफ्ता
6	मांग पत्र को अंतिम रूप देना	संयुक्त आयुक्त पुलिस/ प्रावधान और रसद	उसी दिन
7	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए पुलिस मुख्यालय को मांगपत्र भेजा गया	निरीक्षक	उसी दिन
8	पुलिस मुख्यालय स्तर पर मांग पत्र की जांच	कलर्क-इंस्पेक्टर - प्रशासन एसीपी - डीसीपी—एफए- अतिरिक्त सीपी— संयुक्त सीपी-जिए विशेष सीपी/पी एंड एल	एक महीना
9	पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गये मांगपत्र के विरुध सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन	एसीपी/जीए	एक दिन
10	निरीक्षक प्रशासन द्वारा अनुमोदित और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किये गये मामलो के रसीद	निरीक्षक/प्रशासन/ प्रावधान और रसद	उसी दिन
11	वरिष्ठ अधिकारी मांग पत्र के अनोमोदन का अध्यन करते है तथा उस पर कार्यवाही के लिए योग्यता के आधार पर अपनी टिपणी देते है	वरिष्ठ अधिकारी	उसी दिन
12	GeM पोर्टल पर योग्यता के अनुसार ई- बोली के माध्यम से अनुमोदित वास्तुओ और मात्रा के लिए खरीद परिक्रिया शुरू की गयी और कोंडल ओपचारिकाताओ को पूरा किया गया (आमंत्रण और अन्य ओपचारिकाताओ कर तारीख से बोली प्रस्तुत करने के लिए 21 दिन	इंस्पेक्टर/प्रशासन/ सीएसए	दो से तीन महिना
13	सक्षम अधिकारी की व्यय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए मामला/प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया	एसीपी—डीसीपी— अतिरिक्त सीपी— संयुक्त सीपी/पी एंड एल	एक सप्ताह के भीतर
14	सक्षम अधिकारी की व्यय स्वीकृति करने के लिए मामला/प्रस्ताव के जांच के गयी तथा पी एंड एल को सूचित किया गया	क्लर्क—इंस्पेक्टर— एडमिन—एसीपी—डीसीपी —एफए—अतिरिक्त सीपी —संयुक्त सीपी—विशेष	एक माह

		सीपी	
15	निरीक्षक प्रशासन द्वारा व्यय स्वीकृति की रसीद तथा वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना	इंस्पेक्टर /प्रशासन/पी एंड एल	एक ही दिन
16	व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद , मामला सफल संविदा बोलीदाता को GeM पोर्टल के माध्यम से आपूर्ति आदेश जारी करने के लिए वरिष्ठ कार्यालयों के अवलोकन और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है	लिपिक	दो दिन
17	ई-बोली के आधार पर सफल बोलीदाता को आपूर्ति/अनुबंध GeM पोर्टल पर उपलब्ध कराना	लिपिक	दो दिन
18	पर्दर्शन सुरक्षा प्राप्त करना और पी एंड एल स्टोर्स में आपूर्ति की रसीद प्राप्त करना	क्लर्क एंव प्रभारी	14 दिनों के भीतर
19	सर्वेक्षण समिति/ तकनीकी समिति वस्तुओं का निरीक्षण करती है	सर्वेक्षण समिति/ तकनीकी समिति	सात दिन
20	स्टॉक में सामान लेने के बाद सड़क प्रमाण पत्र के माध्यम से संबंधित लोगों को वितरित किया गया	प्रभारी स्टोर	दो दिन

(जी) विशेष शाखा

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा का (एपीपी शाखा) पासपोर्ट सत्यापन अनुभाग, ऑनलाइन प्राप्त पासपोर्ट के सत्यापन से सम्बन्धित है। पासपोर्ट आवेदन पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके), क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों (आरपीओ) और सम्बंधित दूतावास/वाणिज्य दूतावास से सीधे टैबलेट पर प्राप्त होते हैं जिन्हें आवेदकों के सत्यापन के लिए जाँच अधिकारी (ई.ओ.)को आबंटित किया गया है। सत्यापन पूरा करने के बाद, जाँच अधिकारी सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करता है और इसे इंस्पेक्टर जॉन को भेज देता है। उसके बाद इंस्पेक्टर जॉन उचित सत्यापन के बाद उसे जोनल एसीपी को भेजता है, जो डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट)का उपयोग करके सत्यापन रिपोर्ट को मंजूरी देता है और रिपोर्ट क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, विदेश मंत्रालय या सम्बंधित प्राधिकारी को सौंपता है। टैबलेट की शुरुआत के बाद से, पासपोर्ट सत्यापन को पूरा करना और 5 दिनों के भीतर सम्बंधित आरपीओ/प्राधिकरण को जमा करना आवश्यक है। प्रतिदिन औसतन 1800-2000 पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन प्राप्त होते हैं।

एसीपी शाखा "ओ" पास (अन्य देशों और अन्य राज्यों से सत्यापन के लिए प्राप्त पासपोर्ट आवेदन), एनओआरआई (भारत लौटने की कोई बाध्यता नहीं) और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, आरटी आई और ई-मेल से प्राप्त कार्यों को भी करती है। आवेदन इस कार्यालय की ई-मेल आईडी यानि dcp-splbranch-dl@nic.in और dpapp.sb@delhipolice.gov.in पर अपना फीडबैक भेज सकते हैं। वे अपने प्रश्न लैंडलाइन नम्बर यानि 011-23230577 पर भी पूछ सकते हैं।

(एच) दिल्ली पुलिस के अंग्रेजी शाखाओं / लेखा शाखाओं में पर्यवेक्षण और जवाब देही के प्रणाली सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रक्रिया कार्यपद्धति रूप से अपनाई जाती है : -

मामले, आमतौर पर संबंधित जिलों / इकाइयों के निरीक्षक की देखरेख में धारा / शाखा / डेस्क स्तर पर संसाधित किए जाते हैं और फाइलें संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त / अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त / पुलिस उपायुक्त / अतिरिक्त आयुक्त को सौंपी जाती हैं। प्रत्येक मामले की आवश्यकता के अनुसार पुलिस / संयुक्त पुलिस आयुक्त / विशेष पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त दिल्ली। खातों में मामलों को फाइलें वित्तीय आयुक्त पुलिस आयुक्त और एकीकृत वित्तीय सलाहकार को प्रत्येक मामले की आवश्यकता के अनुसार भेजी जा रही हैं।

(I) नौकर के पंजीकरण और सत्यापन के लिए प्रक्रिया

नियोक्ताओं की सुविधा के लिए, नौकर का सत्यापन इलाके के सिपाहियों के माध्यम से किया जाएगा। वह नियोक्ता के आवासों में जाएगा, उनसे फॉर्म भरने के लिए अनुरोध करेगा और इलाके में गश्त ड्यूटी खत्म होने के बाद थाने में विभाग के अधिकारियों को फॉर्म वापस कर देगा। इस महत्वपूर्ण मामले पर विभाग के अधिकारी / थाना प्रभारी द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

विभाग के अधिकारी और इलाके के गश्ती सिपाहियों को समय-समय पर संयुक्त रूप से इस काम को करने की आवश्यकता होगी। वे अपने साथ पर्याप्त संख्या में फॉर्म (परिशिष्ट 'ए') ले जाएंगे, कर्मचारियों के घरों में जाएंगे और सभी निजी / घरेलू नौकरों / टेंट-हाउसों में काम करने वाले/ आकस्मिक श्रमिकों, हलवाई की दुकानों, आकस्मिक मजदूरों, प्लंबर के लिए फॉर्म की तीन प्रतियाँ भरी जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन और निवासी / बाजार कल्याण संघ द्वारा नियुक्त चौकीदार के लिए भी। उनकी तस्वीरों की एक प्रति पुलिस थानों में रखी जाएगी और उनके फॉर्म नौकर सत्यापन रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे और संबंधित पुलिस स्टेशन को, प्रतिलिपि में, अजनबी रोल के सत्यापन के लिए भेजे जाएंगे। चिंतित थाना प्रभारी अपराध रिकॉर्ड कार्यालय से अपने पूर्ववृत्त की जांच करेंगे, चाहे वे दिल्ली में किसी भी मामले में शामिल हों या अन्यथा।

1.पंजीकरण: -

नियोक्ताओं की सुविधा के लिए, सेवक पंजीकरण प्रपत्र जैसा कि **अनुबंध- 'ए'** में दिखाया गया है।

दिल्ली पुलिस की वेबसाइट www.delhipolice.nic.in पर उपलब्ध कराए गए हैं और सभी पुलिस स्टेशनों में इसकी प्रतियां उपलब्ध हैं। नियोक्ता अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में अपने कर्मचारियों के संबंध में विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा कर सकते हैं और उसी के लिए एक रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इलाके के अधिकारी नियोक्ता के निवास पर भी जा सकते हैं, उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वे फॉर्म भरें और संबंधित पुलिस स्टेशन में जमा करें।

घरेलू नौकर, निजी कर्मचारी, प्लंबर, चौकीदारों आदि के विवरणों के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा: -

1. पुलिस स्टेशन में प्राप्त प्रत्येक पूर्ण किए गए फॉर्म की एक रसीद नियोक्ता को दी जानी चाहिए।
2. एसआरआर नंबर जिसपर रजिस्टर में विवरण दर्ज किया गया है रसीद पर उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. दिल्ली के निवासी कर्मचारियों का सत्यापन संबंधित पुलिस स्टेशन द्वारा समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। इन पृष्ठताछ का परिणाम रजिस्टर के संबंधित कॉलम में दर्ज किया जाएगा।
4. जिलों के सभी आउट-स्टेशन सेवक पंजीकरण फॉर्म डीसीपी कार्यालय से केंद्रीय रूप से भेजे जाने चाहिए और सत्यापन प्राप्त नहीं होने पर संबंधित एसपी को समय-समय पर अनुस्मारक जारी किए जाने चाहिए।
5. व्यक्ति के पते को सत्यापित करने के लिए, संबंधित राज्य की मतदाता सूची को संबंधित राज्य / चुनाव आयोग की वेबसाइट से भी जांचा जाना चाहिए।

सत्यापन के परिणाम प्राप्त होने पर, नौकर पंजीकरण रजिस्टर के उपयुक्त कॉलम में एक प्रविष्टि की जाएगी और नियोक्ताओं को भी उचित रसीद के तहत परिणाम की सूचना दी जाएगी।

(जे) विभागीय जाँच प्रकोष्ठ

दिल्ली पुलिस में विभागीय जाँच प्रकोष्ठ की स्थापना भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आदेश संख्या 14014/41/85-यूटीपी, दिनांक 09/04/86 के तहत की गई थी। वर्तमान में यह 8वीं मंजिल, थाना बाराखम्भा रोड बिल्डिंग, नई दिल्ली पर कार्यरत है।

स्थायी आदेश संख्या Vig. & Pub. TPT./11/2022 के अनुसार, सतर्कता जाँच से उत्पन्न होने वाली विभागीय जाँच और ऐसी अन्य विभागीय जांच, जिन्हें पुलिस आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाये, समय-समय पर इस प्रकोष्ठ की कार्यात्मक शक्ति के आधार पर और अन्य प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के अनुसार, केंद्रीय रूप से संचालित की जा रही है। दिल्ली पुलिस (सजा एवं अपील) नियम-1980, अधीनस्थ रैंक के सभी अधिकारियों और कर्मियों (सिपाही से निरीक्षक) पर लागू होता है।

जिला/इकाइयाँ दिल्ली पुलिस आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना विभागीय जांच (Departmental Enquiries) सीधे विभागीय जाँच प्रकोष्ठ को नहीं भेज सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, उपायुक्त जिला/इकाई उन विभागीय जाँच को जिन्हें विभागीय जाँच प्रकोष्ठ में स्थानांतरित करना आवश्यक है के सम्बन्ध में उचित अनुरोध दिल्ली पुलिस आयुक्त को सम्बंधित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त/विशेष पुलिस आयुक्त के माध्यम से भेज सकते हैं। हालांकि व्यापक मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है जिसके आधार पर विभागीय जाँच (Departmental Enquiries) को विभागीय जाँच प्रकोष्ठ में स्थानांतरित किया जाये, इसे सम्बंधित अधिकारियों के निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। पर्यवेक्षी अधिकारियों को शुरू की गई विभागीय जाँच की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है और उचित मामलों में वे विभागीय जाँच को स्थानांतरित करने के लिए स्वयं कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

(के) इओडब्लू (आर्थिक अपराध शाखा)

क्र. सं.	कार्ययोजना	कार्यवाही का स्तर	समय सीमा
1.	ऑनलाइन, डाक द्वारा व व्यक्तिगत रूप से शिकायतों का लेनदेन	डायरी शाखा	एक दिन
2.	प्राप्त शिकायत को शिकायत शाखा द्वारा एक विशेष संख्या प्रदान करना	प्रभारी शिकायत शाखा	एक दिन
3.	शिकायतों के निबटान हेतु उपयुक्त अनुभाग को प्रेषित करना	एसीपी/ अनुभाग	1-3 दिन
4.	शिकायत जांच अधिकारी को अंकित करना	उच्च अधिकारी	एक ही दिन में
5.	शिकायत का समय	जांच अधिकारी	14 दिन
6.	शिकायत को उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना	डीसीपी/आर्थिक अपराध शाखा एवम विशेष कमिश्नर	जांच सप्ताह होने के तुरन्त बाद एवम समय समय पर
7.	एसीपी द्वारा कार्यवाही की रिपोर्ट	रीडर से अनुभाग प्रमुख तक	जितना जल्दी संभव हो सके
8.	जांच पूरी होने के बाद दी गयी टिप्पणी के अनुसार	डीसीपी/इओडब्लू	उसी दिन या अधिकतम दो से तीन दिन
9.	शिकायतकर्ता को सूचना देना	रीडर/अनुभाग प्रमुख	तीन से सात दिन
10.	यदि एफ आई आर दर्ज होती है तो जांच शुरू	भारतीय न्याय दंड संहिता	भारतीय न्याय दंड संहिता

	की जाती है	के अनुसार	के नियम के अनुसार
--	------------	-----------	-------------------